



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220599
CG-DL-E-20072020-220599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]
No. 170]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/आषाढ़ 29, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASADHA 29, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
शुद्धिपत्र अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020
मामला संख्या (एसजी) 01/2020

विषय : भारत में “सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं” के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – अंतिम जांच परिणाम – सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 और सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 – के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में।

फा. सं. 22/1/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त पाटनरोधी जाँच के संबंध में अधिसूचना सं. 22/1/2020-डीजीटीआर दिनांक 18.7.2020 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की है।

अंतिम जांच परिणाम के पैरा 63 (viii) में निम्न के रूप में पढ़ने के लिए सही किया गया है:

कीमत में कटौती : यह देखा जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क को शामिल किए बिना, आयातों की कामतों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती होना जारी है और इसे गंभीर क्षति हो रहा है।

| विवरण | इकाई | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | अप्रैल 19 – सितं. 19 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| आयातों का पहुंच मूल्य | | | | | |
| सोलर सैल | रू./वाट | 15.42 | 13.68 | 8.95 | 8.76 |
| घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति | | | | | |
| सोलर सैल | रू./वाट (सूचीबद्ध) | 100 | 78 | 39 | 37 |
| कीमत कटौती (%) | | | | | |
| सोलर सैल | % रेंज | 55-65 | 35-45 | 5-15 | 0-10 |

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कीमत में कटौती का विश्लेषण के संबंध में यह उल्लेख करते हुए आपत्ति उठायी है कि कीमत में कटौती का विश्लेषण विचाराधीन उत्पाद की पहुंच मूल्य में रक्षोपाय शुल्क को जोड़े जाने के बाद किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूंकि यह क्षति के फिर से होने को रोकने के लिए रक्षोपाय शुल्क का विस्तार किए जाने की जांच करने के लिए एक समीक्षा है अतः पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

बिद्युत बिहारी स्वैन, महानिदेशक (रक्षोपाय)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

Case No. (SG) 01/2020

Subject: Final Findings of review investigation for continued imposition of Safeguard duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India - Proceedings under the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 - Reg.

F. No.22/1/2020-DGTR:—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duties) Rules, 1997, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Final Finding Notification No. 22/1/2020-DGTR dated 18.7.2020, in respect of the above Safeguard investigation.

The para 63 (viii) of the finding is corrected to read as under:

Price Undercutting: It can be seen that without the inclusion of safeguard duty, the prices of imports continue to undercut the selling price of the Domestic Industry and cause serious injury to it.

| Particulars | Unit | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | April 19-Sept. 19 |
|---|--------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Landed Value of Imports | | | | | |
| Solar Cells | Rs./Watt | 15.42 | 13.68 | 8.95 | 8.76 |
| Net Sales Realisation of Domestic Industry | | | | | |
| Solar Cells | Rs./Watt (Indexed) | 100 | 78 | 39 | 37 |
| Price Undercutting | | | | | |
| Solar Cells | % Range | 55-65 | 35-45 | 5-15 | 0-10 |

Some interested parties have raised an objection with respect to the price undercutting analysis stating that the price undercutting should be analyzed after addition of safeguard duty into the landed value of the PUC. In this regard, it is noted that this being a review to examine the extension of safeguard duty to prevent recurrence of injury the impact of imports without Safeguard Duty needs to be evaluated.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Director General (Safeguard)